



"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता" -वेडेल फिलिपा

# दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 24 मार्च 2026 मंगलवार

## सम्पादकीय

### युद्ध के खतरे और भारत

पश्चिम एशिया में ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद दिनोंदिन हालात जटिल होते जा रहे हैं। साफ है कि युद्ध का प्रत्यक्ष असर भले ही हमले की जड़ में आए देशों में पड़ रहा हो, लेकिन इसकी वजह से अब दूसरे बेसे देश भी प्रभावित होने लगे हैं, जो अपनी कई जरूरतों के लिए मध्यपूर्व के देशों पर कम या ज्यादा निर्भर हैं। उदाहरण के तौर पर ईरान ने जब से होर्मुज जलमार्ग को बाधित किया है, तब से उस रास्ते से तेल और गैस लेकर जाने वाले लगभग सभी देशों के जहाजों का भी रास्ता बंद है। कुछ खास स्थितियों में आंशिक इजाजत दी जा रही है, लेकिन उससे सहारे आने वाले दिनों के व्यापक संकट को लंबे समय तक नहीं टाला जा सकता है।

तेल और गैस की आपूर्ति में भारी कमी की वजह से उपजे मुश्किल से निपटने के लिए भारत ने रूस सहित अन्य विकल्पों की ओर रुख किया है, मगर इससे स्थितियों को सामान्य बनाने में सीमित मदद ही मिलेगी। यह बेवजह नहीं है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच भारत में भी उच्च श्रेणी के पेट्रोल में करीब दो रुपए और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को बचे जाने वाले डीजल में बाईस रुपए की बढ़ोतरी की गई। हालांकि सामान्य पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतों में फिजिकल मुश्किल है कि आने वाले कितने तक इनके दाम स्थिर रहेंगे। मसलन, अगर भारी उद्योगों और बड़ी मशीनों के संचालन में इस्तेमाल में आने वाले औद्योगिक डीजल की कीमतों में खासी बढ़ोतरी हुई है, तो इसका सीधा प्रभाव उत्पादन की लागत पर पड़ेगा। ऐसे में जब औद्योगिक कंपनियों के मुनाफे में कमी आएगी, तो स्वाभाविक रूप से इसके असर से कई अन्य सामान महंगे हो सकते हैं।

रसाई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित होने के कारण लोगों को पहले ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आम उपयोग के पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी होती है, तो यह कोई हैरानी की बात नहीं होगी। इसके बाद इसका असर माल दुलाई पर पड़ेगा और बाजार में खाने-पीने की चीजों की महंगाई भी बढ़ सकती है।

दरअसल, भारत अपनी जरूरत के कच्चे तेल और गैस के लिए खाड़ी देशों से होने वाली आपूर्ति पर काफी हद तक निर्भर है। जब से ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है, उसके बाद भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में वहां से कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति पर व्यापक असर पड़ा है।

एक ओर प्रभावित देशों की ओर से यह उम्मीद की जा रही है कि किसी भी हाल में वार्ता के जरिए संश्लेषण का हल निकाला जाए और युद्ध रुके, ताकि प्रभावित देशों में स्थिति और ज्यादा न बिगड़े। दूसरी ओर, हालात यह है कि अब युद्ध में शामिल दोनों पक्षों की ओर से बड़े पैमाने पर तेल टिकानों को भी निशाना बनाया जाने लगा है और व्यापक तबाही सामने आ रही है। जाहिर है, इससे सीधे तौर पर मध्यपूर्व के देशों से अन्य देशों के लिए तेल और गैस की आपूर्ति टप पड़ेगी तथा इससे संकट का दायरा विस्तृत होगा।

भारत के सामने जो हालात पैदा हो रहे हैं, उसमें सरकार को हरे स्तर पर कूटनीतिक पहल करके कच्चे तेल और रसाई गैस की आपूर्ति का रास्ता तय करने को प्राथमिकता देने की जरूरत है। अगर इस मोर्चे पर टालमटोल का रुख अखिरात किया गया, तो आने वाले दिनों में संकट का अंदाजा लगाया जा सकता है।

किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, समुद्री मार्ग, पर्वत, रेगिस्तान और सीमाएं यह तय करती हैं कि वहां की राजनीति, सुरक्षा नीति और कूटनीति किस दिशा में विकसित होगी। दक्षिण-पश्चिम एशिया, दक्षिण-पूर्वी यूरोप और उत्तर-पूर्वी अफ्रीका तक विस्तारित मध्यपूर्व की कोई स्पष्ट और सर्वमान्य भौगोलिक सीमा नहीं है। भौगोलिक जटिलताओं से प्रभावित इस क्षेत्र में इतिहास, धर्म और बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों ने वैश्विक राजनीति को गहरी संभावित किया है। उर्जा संसाधनों की प्रचुरता, सामरिक समुद्री मार्गों की उपस्थिति और महाशक्तियों के परस्पर हितां के टकराव ने मध्यपूर्व की राजनीतिक परिस्थितियों को और जटिल बना दिया है। यह देखा महत्वपूर्ण होगा कि स्थितियां कब सहज होंगी।

# पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की दशा-दिशा

—कमलेश पाण्डेय—

देश के पश्चिम बंगाल समेत असम, केरल, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी जैसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसके मतदानभरिगणम भाजपा नीत एनडीए की भावी रीति-नीति और सगणों के सामाजिक-राजनीतिक मंत्रियों को तय करने। बताया जाता है कि यदि इन चुनावों को भाजपा नीत गठबंधन जीत जाता है तो अब ओबीसी-दलित वोटों को रिश्ता के लिए सगण विरोधी एजेंडों को इतनीजान पूर्वक धार देना!

ऐसा इसलिए कि सामान्य जातियों से जुड़े सगण वोटर ही भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं। लेकिन ओबीसी प्रश्नमन्त्री नरेंद्र मोदी की सरकार के रहते हुए भी जिस तरह से सगण विरोधी पूजोसी इक्विटी बिल लाया गया है, उससे सामान्य जातियों के लोग असंत सगण समुदाय एक बड़ा तबका अपनी मुख्य पार्टी भाजपा से काफी नाराज हैं और बदलती राजनीति के बीच वे किंभर करवट लेगे, यह बात पूरी तरह से चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा।

राजनीतिक मामलों के जनकार बताते हैं कि अपने हिंदूत्व के एजेंडे को धार देने के लिए भाजपा कांग्रेसी राज और समाजवादी राज की रीति, ओबीसी, अल्पसंख्यक व भाषाई धारा समन्वही नीतियों को और अधिक धार दे रही है। आरक्षण, जातीय जुगजुगता, एससी-एसटी एजेंडे से जुड़े पदान्ति प्रक्रिया, कमांड मिडर संस्करण जैसे नीतियों में पहले की संस्कारों में और अब की सरकार में कोई अंतर नहीं आया है।

कोह में खाज यह कि भाजपा अपने हिंदूत्व के एजेंडे से मुक्तकी प्रति हो रही है। ऐसे में सत्ता के जातीय, सांप्रदायिक और भाषाई-अंत्राय की मानसिकता में कोई बदलाव न देखे हुए का समाजिक इंजन वर्य यानी सगण समुदाय भाजपा से काफी नाराज है और पूजोसी इक्विटी बिल ने आम में घी का काम किया है।

कृि सगण वोट कमी कांयस,



गणमूल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों का भी कोर वोट बैंक हुआ करता था, और इनकी दलित-ओबीसी आरक्षण व अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीतियों से आंजित होकर भाजपा के आरक्षक मंडल विरोधी कम्पनडलवाद पर क्रिदा हो चुका था, वह मोदी-शाह युग में एक के बाद दूसरे झटके लगे रहे वर्य सियासी विकल्प बंद रहा है। कृि भाजपा नेतृत्व पूजोपतियों के इशारे पर ब्राह्मण-राजपूत नेतृत्व को दरकिनारा करते हुए ओबीसी-दलित नेतृत्व को मजबूत कर रहा है, इससे भी सगण वॉ में नाराजगी है।

यही वजह है कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भाजपा के खिलाफ उभरने सगण प्रतिरोध को पूरी तरह से अंदर ही अंदर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका दलित- ओबीसी-अल्पसंख्यक कोर वोट बैंक नाराज भी न हो और सगण भी उनकी ओर लौट जाए, ताकि अखतक की हारी हुई बाजी को पुन जीता जा सके और यत्र तत्र जीती हुई बाजी को बरकरार रखा जा सके। हालांकि, अब से अपनी कोशिशों में कितने कामयाब होंगे, यह तो मतदान मगणना बाद ही पता चल पाएगा।

वही, कतिपय राजकीयों में

विरलपका को मानना है कि देश के पश्चिम बंगाल समेत असम, केरल, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी जैसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के चुनाव परिणाम सगणों के सामाजिक-राजनीतिक मंत्रियों को तय नहीं करेगे, भले ही भाजपा इन चुनावों में पश्चिम बंगाल और असम जीत जाए और तमिलनाडु, केरल व पुद्दुचेरी में पहले से ज्यादा मजबूत होकर जीतें। क्योंकि पूजोसी इक्विटी बिल के वाद उभरते सगण जनक्रांि का डैमैज-कंट्रोल करने के लिए भाजपा-आरक्षक संघ के रणनीतिकार जुट गए हैं, हालांकि उन्हें भी यह आशंका है कि ये चुनाव भाजपा के सगण वोट बैंक के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा की घड़ी हैं। वही, भाजपा की ओर किचने दलित-ओबीसी वोटर लौटते हैं, इससे भाजपा को सियासी तंदरुस्ती मिलेगी।

भाजपी की सगण लॉबी का कहना है कि अब भी सगण वोट पार्टी के कोर संपीटर उभरने हुए हैं, क्योंकि उनके पास भाजपा से उन्मा विकल्प मौजूद नहीं है। जबकि भाजपा अपनी चुनावी जीत के लिए दलित, आदिवासी और ओबीसी वोटों पर ही निर्भर करती है। इसलिए वह सभी समुदायों के बीच राष्ट्रवादी तालमेल स्थापित में जुटी हुई है। वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम देश, भारत के खिलाफ नहीं खड़े हों, इसलिए भाजपा

ने भी कुछ बदलावों के साथ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीतियों को अपना लिया है।

असल, यदि 5 राज्यों में हो रहे चुनावों की चुनावी पृष्ठभूमि पर नजर डाली जाव तो 2026 में पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए मतदान 23-29 अंश 2026 को होंगे। वही, तमिलनाडु की 126 विधानसभा सीटों, तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों, केरल की 140 विधानसभा सीटों और पुद्दुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए भी चुनाव होंगे। इन चुनावों में भाजपा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और असम पर फोकस कर रही है। क्योंकि जहां पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 77 सीटें मिली थीं। वही, असम में भाजपा की सत्ता बरकरार रहा गई थी और अभी वहां भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी है।

इसलिए, जहां तक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सगणों की भूमिका की बात है तो भाजपा को सगण यानी ब्राह्मण, कायस्थ, वैद्य आदि से मजबूत समर्थन मिलता बताया जा रहा है। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर सभी जातियों व धर्मों को मिलालकर 61: सगण वोट है। वही पश्चिम बंगाल में भाजपा 58: हिंदू वोट फोर्मुहाइर से सगणों को रश्नतानतरी के रूप में साध रही है। जबकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेतृत्व में सुवाई सत्ता के शीर्ष पर

सगण कायम है, जबकि जीत के फेडरलसंख्यक-दलित-अल्पसंख्यक-ओबीसी वोट मुख्य है।

इसलिए भाजपा भी पश्चिम बंगाल में सगणों को टीएमसी की सत्ता से खींचकर अपनी ओर करना चाहती है और ओबीसी-दलित-आदिवासी वोटों को भी अपने पाले में करने में जुटी हुई है, जबकि अल्पसंख्यक वोट के रयस्ता फैलाने हेतु उसके गुप्त इशारे पर वहां की लोकल अल्पसंख्यक पार्टी ताल ठोक चुकी है। वही बंगाल अस्मिता का संघल कितना मुखर होगा, घुसपैठियों का मुद्दा कितना रंग लागेगा, वह मतदान रंठ और चुनाव परिणाम से ही पता चलेगा।

वही, जहां तक पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के परिणाम की बात है तो भाजपा की जीत से सगणों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन उनका सामाजिक मंत्रिय भाजपा की राष्ट्रीय नीतियों यथा-आरक्षण, जाति जुगजुगता आदि पर ही निर्भर करेगा। वही, असम में भी राव्य काले लागू होंगी, क्योंकि वहाँ तो भाजपा पहले से ही सत्ता में है। वही, तमिलनाडु और केरल में सगण प्रभाव कम है, इसलिए 5 राज्यों की जीत से सगण गठबंधन मजबूत होगा, न कि सगणों का राजनीतिक-सामाजिक मंत्रिय तय होगा। उत्तरप्रदेश, बिहार, मह्यदेश, राजस्थान, गुजरात आदि के भावी विधानसभा और आम चुनाव 2029 के संधान, मतदान और चुनाव परिणाम वास्तविक तौर पर सगणों के सामाजिक-राजनीतिक मंत्रिय को तय करेगे (यही वजह है कि भाजपा की पश्चिम बंगाल में जीत से सगण ईडव्यूएस आरक्षण में भी सीधा असर पड़ने की संभावना कम है, क्योंकि यह केंद्र सरकार के नीति धर्म में आता है। राव्य स्तर पर भाजपा सगण समर्थन को मजबूत करने वाली नीतियां ला सकती है, लेकिन 10 आंशिक रूप से कमजोर सगण आरक्षण राष्ट्रीय कानून श्रेतों में बरसे हैं। भाजपा इन्हें रश्नतानी एकारा के जरिए साध रही है, जो 2021 के विधानसभा चुनाव में 68: हिंदू वोट, जिन्हें सगण वोट प्रमुख रहे, भाजपा को मिले थे, जिससे वह 77 सीटें जीत पाई है।

वर्तमान आरक्षण 39: है, जिसमें अनुसूचित जाति 22: अनुसूचित जनजाति 6: अन्य पिछड़ा वर्ग 10: आंशिक रूप से कमजोर वर्ग 1: है, जो 50 की अनुमत्य सीमा से 11: कम है। कृि भाजपा को केंद्र में ईडव्यूएस आरक्षण को साल 2019 से लागू कर चुकी है, जो सगणों के लिए आंशिक आधार पर है, जाति आधार पर नहीं। यही वजह है कि भाजपा यदि पश्चिम बंगाल की सत्ता में आती है तो इसका संघलित प्रभाव राज्य नीति पर भी पड़ेगा।

चर्चा है कि पश्चिम बंगाल की जीत पर भाजपा ईडव्यूएस कोटा बढ़ा सकती है और सगण-केंद्रित योजनाएं जो शिक्षा, नौकरी से जुड़ी हैं, वहां ला सकती है, लेकिन सुयोग्य कोट की 50: सीमा बाधा बननी। जहां तक राजनीतिक बात है तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से सगण वोट मजबूत होगा, लेकिन दलित-ओबीसी विरोध बढ़ सकता है, जैसा पूजोसी निधामों पर देखा गया। इसका राष्ट्रीय लिक यह है कि पश्चिम बंगाल की जीत भाजपा नीत एनडीए को मजबूती देगी, जिससे संसदीय बहुमत से ईडव्यूएस विचार संभव है, पर सुयोग्य कोट की चुनौती बनी रहेगी।

चुनाव पूर्व सर्वे के रूझान चुगाली कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में सगण वोट भाजपा के लिए एक समर्थन आधार बने रहेंगे, लेकिन कमी भूमिका निर्णायक से अधिक सहजक होगी। ताजा ओपिनियन पोल्स के अनुसार, सगण हिंदू वोट का लगभग 33: भाजपा को मिल सकता है, जबकि 20: अभी अनिर्णय की स्थिति में है, यानी अनडिहासाडेड है। जहां तक सगण वोट के आकार की बात है तो पश्चिम बंगाल में हिंदू सगण यानी ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य मतदाता, कुल होंगे 15-20: हैं, जो मुख्यतः शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बरसे हैं। भाजपा इन्हें रश्नतानी एकारा के जरिए साध रही है, जो 2021 के विधानसभा चुनाव में 68: हिंदू वोट, जिन्हें सगण वोट प्रमुख रहे, भाजपा को मिले थे, जिससे वह 77 सीटें जीत पाई है।

# तेज होती हथियारों की होड़ और विश्व व्यवस्था

—ललित गर्ग—

तेज होती हथियारों की होड़ और अस्थिर होती विश्व व्यवस्था आज मानव सभ्यता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर खड़ी हुई है। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां युद्ध केवल सीमाओं पर लड़े जाने वाले संघर्ष नहीं रह गए हैं, बल्कि उनका प्रभाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा व्यवस्था, पर्यावरण, सुविधा-संतुलन, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता तक पहुंच रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, ईरान और इजरायल के बीच हमलों का नया दौर, अमेरिका की रणनीतिक भूमिका, रूस-यूक्रेन युद्ध और चीन-ताइवान तनाव जैसे अनेक घटनाक्रम मिलकर यह संकेत दे रहे हैं कि दुनिया एक बार फिर हथियारों की दौड़ और शक्ति संतुलन की राजनीति की ओर लौट रही है। यह स्थिति केवल राजनीतिक या सामरिक नहीं, बल्कि मानवीय संकट का संकेत भी है, क्योंकि जब दुनिया हथियारों पर ज्यादा खर्च करती है तो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्र पीछे छूट जाते हैं।

आज हर देश अपनी सुरक्षा के नाम पर हथियार खरीद रहा है, सेना को मजबूत कर रहा है और सैन्य बजट बढ़ा रहा है। यह एक देशी दौड़ बन गई है जिसमें कोई भी हारेंगे पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन विद्वानों का मानना है कि जितने अधिक हथियार खड़े रहेंगे, दुनिया उतनी ही अस्थिर रहेगी। दुनिया की सुरक्षा की यह मानसिकता वास्तव में अंधकृषा का ही परिणाम है। एक देश हथियार बढ़ाता है तो दूसरा देश भी हथियार बढ़ाता है और इस तरह एक अविनाश का चक्रवर्तन बन जाता है। यह अविनाश का चक्रवर्तन ही दुनिया को अस्थिर करता है। विश्वकोश का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में दुनिया का सैन्य खर्च कई गुना बढ़ जाएगा और यह देश मानसिक विकास के बजाय विनाश की तैयारी में खर्च होगा। यह स्थिति मानव सभ्यता के लिए शूण संकेत नहीं है। पश्चिम एशिया का संकट इस समय दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता दिखाई दे रहा है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते हमले, समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर तनाव और बढ़े



देशों की प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी ने इस क्षेत्र को युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप द्वारा समुद्री मार्ग खोलने की चेतावनी को खारिज करते हुए ईरान ने इजरायल पर हमलों का नया दौर शुरू किया है, जिससे यह संकट और अधिक गंभीर हो गया है। यदि यह संघर्ष लंबा चलता है तो इसका प्रभाव केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि यह कुछ दुनिया की उर्जा आपूर्ति का केंद्र है।

दुनिया की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल और गैस पर निर्भर है और पश्चिम एशिया तेल उत्पादन का सबसे बड़ा देश है। यदि वह युद्ध बढ़ाता है या समुद्री मार्ग बाधित होता है तो तेल की कीमतें उंची से उड़ेंगी। तेल महंगा होगा तो विकास-डीजल महंगा होगा, परिवहन महंगा होगा, उत्पादन लागत बढ़ेगी और अंततः हर वस्तु महंगी हो जाएगी। यानी एक वैश्विक महंगाई का दौर शुरू हो सकता है। महंगाई बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। इसी के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था भी की ओर धीरे जा सकती है। पहले से ही कई देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और यदि उर्जा संकट बढ़ता है तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी। भारत जैसे देश भी इस स्थिति से अछूते नहीं रह सकते, क्योंकि भारत अपनी उर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। इसी कारणां को देखते हुए भारत सरकार ने उर्जा आपूर्ति,

पेट्रोल-डीजल, गैस और उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। प्रश्नमन्त्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के साथ आपात बैठक कर उर्जा और संपातित संकट को बरकरार रखने और संपातित संकट से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। केवल केंद्र सरकार की तैयारी पर्याप्त नहीं होगी, राज्य सरकारों को भी इस स्थिति को समझते हुए उर्जा संरक्षण, आपूर्ति प्रबंधन और आंतरिक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाने होंगे।

इस पूर्व परिदृश्य में सबसे बड़ी चिंता यह है कि दुनिया युद्ध को रोकने के बजाय उसकी तैयारी ज्यादा कर रही है। युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे रोकना बहुत कठिन होता है। इतिहास गवाह है कि कई युद्ध ऐसे हुए जो कुछ दिनों के लिए शुरू हुए लेकिन वर्षों तक चलते रहे और उन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। यानी यदि पश्चिम एशिया का युद्ध फैलता है तो यह केवल दो या तीन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बड़े देशों की भागीदारी से यह वैश्विक संघर्ष का रूप ले सकता है। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि विश्व के बड़े देश आगे बढ़कर युद्ध विनाश की पहल करें और वार्ता का रास्ता निकालें। अमेरिका की भूमिका इस पूर्व संकट में बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि अमेरिका चाहें तो वह इजरायल पर दबाव डाल सकता है, ईरान के खिलाफ शुरू कर सकता है और

संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से युद्ध विनाश की दिशा में कदम उठा सकता है। कूटनीति का रास्ता हमेशा युद्ध से बेहतर होता है, क्योंकि युद्ध में अंततः नुकसान सभी का होता है। युद्ध में नुकसान मरते हैं, नागरिक मरते हैं, शहर बर्बाद होते हैं, अर्थव्यवस्था टूटती है और आने वाली पीढ़ियां तक उसके दुष्परिणाम झेलती हैं। इसलिए आज दुनिया को हथियारों की दौड़ नहीं, शांति की दौड़ की जरूरत है।

वैश्विक हथियारों की होड़ का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे विकास रुक जाता है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां आज भी लोग गरीब, भूख, बीमारी और अस्थिरा से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने के बजाय हथियारों पर खर्च बढ़ाने में लगे हैं। यह मानवता के साथ एक तरह का अन्याय है। यदि दुनिया का सैन्य बजट का एक छोटा हिस्सा ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च कर दिया जाए तो दुनिया से गरीबी और मूख को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। लेकिन दुनिया से दुनिया की राजनीति अभी भी शक्ति संतुलन और सैन्य प्रतुल्य के इर्द-गिर्द घूम रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व नेतृत्व वह समझे कि असली शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, विज्ञान, शिक्षा और मानव विकास में होती है। जो देश अपने नागरिकों को बेहतर जीवन देता है, वही वास्तव में शक्तिशाली देश होता है। युद्ध और हथियार केवल विनाश लाते हैं, विकास नहीं।

# युद्ध और कला, संस्कृति को नुकसान



—ज्योति मल्होत्रा—

युद्ध है कि युद्ध व संघर्ष में कला-संस्कृति व पुरातत्व से जुड़ी चीजों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। देश के बंटवारे के परिणाम स्वरूप हुई अदला-बदली में सांस्कृतिक कलाकृतियां का भी भारी नुकसान हुआ। ईरान भी हालिया युद्ध की कीमत चुकाने में है। चंडीदास के लिए 9 में दिन-दहाड़े हुई एक हत्या को लेकर पिछले कुछ दिनों से शहर हिला और सन्नाह हुआ है। शहर का बंद हिस्सा, जो अपने लाल सुर्ख गंगानदीयिया फूलों के लिए बेहतर जाना जाता है न कि गीतियों की बोझार के बाद स्थानीय गैरमंदिर के विरोध लाल लहू के रंग से। कृि दलता के कई निष्कर्ष हो सकते हैं, बेहतर होगा कि हम आगे बढ़ें और पास के सेक्टर-10 की बात करें, यहां पिछले कुछ महीनों से ली कॉलेजिएट द्वारा डिजाइन सरकारी संग्रहालय और आर्ट गैलरी में एक आणक किष्म की हिंसा जा रही है। गंभीरता है कि यहां जहां जुलानी ईडव्यूएस जाहाज जो कमी पंजाब के सबसे बड़े संस्कृति एक कला विदाता, 1507 में पेशिया में इतनाली साम्राज्य की नींव रखने वाले जसवंत अहमदीसी डी अनुत्कृत को है। गंगा को भी अनुत्कृत ने 1510 में बीजापुर की संस्कृति से रिया था। इसके महज 16 साल बाद, 1526 में, यही उत्तर भारत के तेमूर शक्ति से पानीपत में अपने ही एक वल्लभम विदाता, इब्राहिम लोदी को हराकर, जबर ही युद्ध को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर डाला था।श्रावज जब हिमारे टीवी क्रीन पर युद्ध के विस्फोटों के दृश्य चल रहे हैं, तो साम्राज्यों के उरुच और पतन और उससे जुड़ी हिंसा को समझना ज्यादा आसान हो जाता है। पंजाब भारत के उन दो राज्यों में से एक है, पेशिया है गंगा, जिसकी शहरी यादें विनाश की बंरता से जुड़ी हैं।

को कम रचना जयादा जरूरी है? शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिकी अब खरार द्वीप पर कब्जा करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि ईरानियों पर दबाव डालकर होर्मुज जल-डमरू को फिर से खोला जा सके, जिससे होकर दुनिया का एक-तिहाई तेल गुजरता है। दरअसल, खरार द्वीप पर तेल-शोध का एक विशाल संयंत्र है, जिसके माध्यम से ईरान के कुल निर्यात का 90 प्रतिशत तेल साफ किया जाता है। 13 मार्च को हुई बमबारी में, ईरान ने तेल सुविधाओं को बखड़ा दिया था। लेकिन जैसे-जैसे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, अमेरिका और अन्य देशों की आंखें तेल की कीमतों के घटने टकाने पर मजबूर करने को और भी कड़े कदम उठा सकते हैं। केंद्र पाल भी लला लला लला के कारण, खरार द्वीप को एक आकंक्षक विकल्प माना जा रहा है। उल्लेखनीय कि यह एनए 500 साल पुराने एक पुर्तगाली मठ का भी स्थान है।कृकृकृ 1507 में पेशिया में इतनाली साम्राज्य की नींव रखने वाले जसवंत अहमदीसी डी अनुत्कृत को है। गंगा को भी अनुत्कृत ने 1510 में बीजापुर की संस्कृति से रिया था। इसके महज 16 साल बाद, 1526 में, यही उत्तर भारत के तेमूर शक्ति से पानीपत में अपने ही एक वल्लभम विदाता, इब्राहिम लोदी को हराकर, जबर ही युद्ध को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर डाला था।श्रावज जब हिमारे टीवी क्रीन पर युद्ध के विस्फोटों के दृश्य चल रहे हैं, तो साम्राज्यों के उरुच और पतन और उससे जुड़ी हिंसा को समझना ज्यादा आसान हो जाता है। पंजाब भारत के उन दो राज्यों में से एक है, पेशिया है गंगा, जिसकी शहरी यादें विनाश की बंरता से जुड़ी हैं।



